SHRI R. K. KHADILKAR : Those whose lands have been occupied for constructing camps or temporary shelter, will be compensated duly.

DR. RANEN SEN : In view of the fact that the refugees are crowding the borders and the State administrations are faced with the heavy additional task of issuing registration cards etc., has the Government any plans to employ persons for this work separately, so that the normal administrative personnel would be free for their ordinary duties ? The West Bengal Government has also suggested such a scheme. What has been the fate of the scheme ?

SHRI R. K. KHADILKAR : In view of the heavy administrative burden on the local administration, the local administration has been further strengthened by recruiting suitable staff to undertake this responsibility.

SHRI D. BASUMATARI : It is not a fact that the camps for the refugees in Assam and and Meghalaya are only in the tribal area and may I know wether there is any scheme for protecting the land of the tribals where it is utilised for the refugees because they are already very backward economically ?

SHRI R.K. KHADILKAR : So far as tribal area on the Assam and Meghalaya borders are concerned where the refugees are now given shelter temporarily, I may say that our scheme is to shift them to a bigger camp and therefore there is no possibility of any ill-feeling or the tribals suffering because of this influx.

गन्ने के मूल्य निर्धारित करना

+

*574. श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगामी मौसम के लिए गन्ने के नियत किये गये मूल्यों की घोषणा कर दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन के कब तक निर्धारित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों से भी परामर्श करना चाहती है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH) : (a) and (b). The basic minimum price payable by sugar factories for sugarcane to be purchased by them during the season 1971-72 (1st October 1971 to 30th September 1972) has not so far been announced, as the Government have decided to watch the position consequent on decontrol of sugar for sometime before taking a final decision.

(c) The minimum sugarcane price is fixed after consulting the State Governments and other interests and authorities concerned.

श्री चन्द्रिका प्रसाद : अध्यक्ष जी, गन्ने की कीमत लकड़ी और कोयले की कीमत से भी गिरी हुई है, जबकि किसान साल भर उसकी खेती में फंसा रहता है, साल भर गर्मी और जाड़े में मेहनत करता है, बिजली और पानी उस पर खर्च करता है...

अध्यक्ष महोदय : आप तो पुराने मैम्बर हैं, सवाल कीजिये ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : जबकि गन्ने की कीमत तय करने में भारत सरकार कोई ध्यान नहीं देती है । कहा जाता है कि राज्य सरकार की राय से गन्ने की कीमत तय की जाती है । मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की राय को नहीं माना जाता है । शुगर की रिकवरी को दृष्टि से जहां पर जो मिलें लगी हुई हैं, वे पचास साल पुरानी हो गई हैं, लोहे का कबाड़ बन कर रह गई है...

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत तय करते समय, जैसा राज्य सरकार का परामर्श था कि 9 रु. 40 पैसे रखी जाय, उसका ध्यान न रखते हुए पिछले साल 9.4 परसेंन्ट और उससे नीचे जितनी रिकवरी आई, उसके लिये 7 रु. 37 पैसे मुकर्रिर की थी । 9.4 परसेन्ट से अगर कम भी थी, 8 परसेन्ट भी थी तो इतना ही रखा गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले से आता हूं, हमारा इलाका पिछड़ा इलाका है, वहां पर शुगर के अलावा कोई इण्डस्ट्री नहीं है, वहा पर सारी मिलें सिक मिलें है, एक तरह से लोहे का अम्बार बनी हुई हैं। जब तक आप उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे गन्ने की इस कीमत से किसानों का फायदा नहीं होने वाला है । जब सरकार किसी बात को टालना चाहती है तो उसके लिए आयोग बना दिया जाता है, उसी तरह का आयोग यहां पर भी बना दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसका राष्ट्रीयकरण करने की कृपा करेगी ।

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले कह चुका हूं कि आयोग भारत सरकार ने बनाया इसलिये ताकि सारे देश के लेविल पर हम फैसला कर सकें। जहां तक स्टेट का सम्बन्ध है, स्टेट कर सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है ।

श्री शिव कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक बार डिबेट का उत्तर देते हुए उस समय के कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो भी मूल्य निर्धारित हो जाएगा राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर के, वह तो किसानों को तत्काल दे दिया जायगा । लेकिन बाजार में अगर चीनी ऊंचे भाव पर बिकेगी तो जो अतिरिक्त राशि होगी वह किसान को दे दी जाएगी । तो क्या वह आधार अब भी कायम है ? या मंत्री जी के परिवर्तित होने से उस में भी परिवर्तिन हो गया ?

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय वह आधार अब भी कायम है । हम जो प्राईस मुकर्रर करते हैं वह कम से कम होती है । उससे ऊपर फैक्ट्रीज देती रही हैं । 16 रु. और 20 रु. का दिया है । हमने 30/40 परसेंट फ्री शुगर सेल के लिये दी और जिस समय कीमतें ज्यादा थीं फ्री शुगर की तों कीमतें ज्यादा भी दी । और जब लेवी प्राइस और फ्री सेल की कीमतें नजदीक आ गयी उसके बाद जो मिनिमम प्राइस थी वह दी गयी, उससे कम नहीं दी ।

लेकिन ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि जो मिनिमम प्राइस है वही दें । उससे उपर भी दे सकते हैं और मिले देती भी हैं ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि हर साल गन्ने के दाम के बारे में कोई निश्चय न होने से गन्ने की खेती की बढोत्तरी होने में दिक्कत होती है जिससे आगे चल कर के हमको फौरन ऐक्सचेंज में नुकसान होता है या जो शुगर का हमारा टार्गेट होता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उसूल बना हुआ है उस पर मंत्री जी को क्या दिक्कत है गन्ने का दाम पहले तय करने में जिससे किसान अपनी गन्ने की खेती बढ़ा सकें ?

श्री शेर सिंह : हम हमेशा यह तय करते हैं फसल से पहले फैसला कर दें । लेकिन इस

बार दिक्कत यह हुई कि चूंकि हमने डी-कंट्रोल करने का फैसला किया तो हम कुछ समय तक देखना चाहते थे कि उसका क्या प्रभाव होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्राईस फिक्स करना चाहते है ताकि किसान को घाटा न रहे। आज प्राइस फिक्स कर दें और कल यह सोचें कि यह प्राइस ठीक नही बल्कि और प्राइस होनी चाहिये थी, तो उसमें दिक्कतें पैदा हो जाती है।

श्री सरजू पांडे : अभी सरकार ने मिल मालिको के दबाव मे आ कर चीनी पर से कंट्रोल हटा लिया जिससे चीनी का दाम बाजार मे बढ़ गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जबसे डीकंट्रोल किया है शुगर का दाम बढ़ा है, गन्ने के दाम निर्धारित करने मे देर क्या है ?

श्री शेर सिंह : यह बिल्कुल गलत है कि हमने मिल मालिको के दबाव मे आ कर कोई फैसला किया।

शुगर प्राइस के बारे में आपने जो कहा, मैं बता दू कि डीकंट्रोल के बाद शुगर की प्राइस बढ़ी नही है, बल्कि कम हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री इसहाक सम्भली : पहले से मार्केट में दाम बढ़ गये हैं। बाजार में जाकर खरीदे तब पता लगे। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज। क्या मजा आता है आपको शोर करने में। यह पार्लियामेंट है। आप मंत्री जी को जवाब पूरा देने दीजिये।

श्री अटल बिहार वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि चीनी के दाम बढ़ गये हैं।

श्री इसहाक सम्भली : गलत इनफारमेशन के आधार पर ही गलत फैसले किये जाते हैं।

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूची है दामो की। अगर आप चाहे तो मैं पढ़ कर सुना सकता हू।

अध्यक्ष महोदय : चीनी का मसला है, बहुत नाजुक है, सोच समझ कर बोलियेगा।

श्री सरजू पांडे : अधिकारी गलत सूचना देते है क्यो कि मुफ्त मे चीनी खाते है।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज। मै बढा तग हूं। आप मेरे नजदीक बैठे है इसलियें बडा डिस्टर्बेंस होता है। मै फोलो नही कर सकता प्रोसीडिंग्स।

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि हर जगह के मेरे पास 15 जून तक के आंकडे हैं।

आसाम मे 24 मई को प्राइस थी 205 रु. और डीकंट्रोल हुआ 25 मई को। और 14 तारीख को 195 रु. प्राइस थी। बिहार मे 200 रु. प्राइस थी, अब 184 रु. है।...

श्री इसहाक सम्भली : यह आप होलसेल प्राइस बता रहे है। रिटेल प्राइस बताइये।

श्री शेर सिंह : ठीक हैं मैं होल सेल प्राइस बता रहा था। आप रिटेल प्राइस भी सुन लीजिये।

रिटेल प्राइस आसाम में 2.15 पैसे थी, अब 2.05 पैसे है। बिहार में 2.12 पै. थी अब 1.95 पै. है। गुजरात में 2.03 पै. थी अब 1.89 पैसे है। देहली में 2.15 पै. थी 24 तारीख को और 14 तारीख को 2.05

पैसे प्रति किलो चीनी की प्राइस थी। (व्यवधान—बिल्कुल गलत है)

श्री इसहाक सम्भली : दिल्ली में चीनी 2.25 पै. मिल रही है। स्पीकर साहब, सुपर बाजार में दाम मालूम कीजिये। मैं जानना चाहता हूं कि वहां चीनी का क्या भाव है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइये।

श्री इसहाक सम्भली : मैं चेलेंज करता हूं आप सुपर बाजार में टेलीफोन करके चीनी के दाम पता लगाइये। (व्यवधान)

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI F. A AHMED) : It appears that the figures quoted by my colleague are not in accordance with the practical experience of hon. members, so far as the prevailing price of sugar is concerned. I shall verify these prices (*Interruptions*).

SHRI INDRAJIT GUPTA : Don't you buy sugar for your own use ? Do Ministers get free supply of sugar or what ? (*Interruptions*).

श्री इसहाक सम्भली : स्पीकर साहब, मेरा पाइंट आफ़ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन आवर में पौइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री इसहाक सम्भली : मिनिस्टर साहब खुद मुतमईन नहीं है। क्या आप इसको वेरीफाई करेंगे।

श्री बी. पी मौर्य : यह गलत बयान दे रहे हैं दिल्ली के बारे में।

MR. SPEAKER : The Minister has said that if there is a difference in price, he will verify it. (*Interruptions*).

SHRI NIMBALKAR : May I know whether in fixing the price of sugarcane only the sugar content in the sugarcane is taken into consideration ? Is it not a fact that there are some sugar factories which have attached distilleries ? Should they not be asked to pay a higher price for their sugarcane ?

अध्यक्ष महोदय : आप कहां से कहां चले गए।...(व्यवधान)...

श्री शेर सिंह : माननीय सदस्य का सवाल सुनाई नही दिया।

श्री एस. एम. बनर्जी : उन्होंने कहा था कि आपने चीनी का डी-कंट्रोल कर दिया और चीनी का दाम बढ़ गया तो उसी हिसाब से शुगरकेन का दाम भी आप बढ़ायेंगे या नहीं और अगर नहीं बढ़ायेंगे उसका कारण क्या है ?

श्री शेर सिंह : जैसा मैंने निवेदन किया, डी-कंट्रोल के बाद कुछ देर वाच करेंगे और उसके बाद प्राइस फिक्स करेंगे।

PROF. S. L. SAKSENA : Is the government aware that if it does not increase the price of sugarcane to at least Rs. 10 per quintal there will be shortage of sguar next year ?

SHRI SHER SINGH : I have no information with regard to sugarcane sown this year. I will make enquiries.

श्री मेंदा सिंह : श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी कहा कि गत वर्ष की नीति थी कि फ्री सेल की चीनी और लेवी की चीनी की दो कीमतें होंगी और दोनों में फ्री सेल की चीनी ज्यादा कीमत पर बिकेगी तो उसमें किसानों को भी हिस्सा दिया जायेगा। तो क्या यह सही है कि पिछले वर्ष फ्री सेल की चीनी ज्यादा कीमत पर बिकी है ? यदि हां, तो भारत सरकार किसानों को

उनका हिस्सा दिलाने के लिए क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री शेर सिंह : जैसा मैंने निवेदन किया कि जब फ्री सेल का प्राइस बहुत ज्यादा थी तब किसानों की ज्यादा प्राइस दी गई लेकिन पिछले साल फ्री सेल की प्राइस और लेवी शुगर की प्राइस में बहुत थोड़ा अन्तर था, कोई विशेष अन्तर नहीं था ।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : This question relates to sugarcane growers and sugarcane prices. Unfortunately, members have dragged in the question of sugarcane cess and spoiled the question. I will put a straight question. Is the hon. Minister going to increase the rate for sugarcane from Rs. 73 to Rs. 100 per ton for a recovery of 9.4 and less ? If not, how will he get sufficient sugarcane for his sugar requirements next year ?

SHRI F. A. AHMED : The price of sugarcane is fixed from time to time. At the time of fixing the price the point mentioned by the hon. Member will be kept in view.

Charges levelled against Food Corporation of India in Rajasthan Assembly

*549. SHRI BIREN DATTA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the charges levelled by some members in the Rajasthan Assembly against the Food Corporation of India regarding bajra purchases from that State ;

(b) if so, what are the charges ;

(c) whether the inquiry had been conducted into these charges ; and

(d) if so, the findings thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(c) Inquiries into the allegations with regard to purchase of bajra by the Food Corporation of India, were made by the F. I. C. and the State Government.

(d) The inquires of the F.I.C. revealed that the allegations were not substantiated. Inquiries by the State Government are still in progress,

STATEMENT

Allegations made against the FCI in Rajasthan Assembly regarding purchase of Bajra.

It generally alleged that :—

(i) There was conspiracy between the F.C I. officials and the traders to cheat the cultivators and the Government ;

(ii) F.C.I.'s staff was rejecting stocks offered by the producers, but purchasing the same from the traders at the procurement price. The traders bought it from the producers at a lower rate and pocketed the difference ; and

(iii) The F.C.I. officials were corrupt and indulging in irregularities.

In addition to these, certain specific allegations were also made in respect of purchases in some of the mandis.

SHRI BIREN DUTTA : In the statement it is stated :—

> "There was conspiracy between the ECI officials and the traders to cheat the cultivators and the Government ;
>
> FCI's staff was rejecting stocks offered by the producers, but purchasing the same from the